सम्पादक के नाम

मोदी सरकार में मंत्री एम.जे.अकबर पर एक दर्जन से भी अधिक महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं जिसके खिलाफ सरकार ने 97 वकीलों की फौज खड़ी की

कमल कुमार

कई लोग ऐसे भी थे जो यह मान रहे थे कि मंत्री अकबर के अफ्रीका से लौटते ही मोदीजी उनसे इस्तीफा लेंगे । कितने मासूम थे वे लोग जो यह सोच रहे थे । ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मोदी इस्तीफा लेंगे ? अजी यह बीजेपी है खांटी की दक्षिणपंथी और अवसरवादी पार्टी । इसके नेताओं को कोई लाज शर्म नहीं बल्कि हर मुद्दे का राजनीतिकरण य्या धर्म से जोड़ना इनकी नीति है ।

भूल गए क्या उन्नाव कांड ? बीजेपी के विधायक ने नाबालिग लड़की का बलात्कार कर उसके पिता की हत्या तक करवा दी उसके वाबजूद भी यह पार्टी उस विधायक के साथ खड़ी थी और इस पार्टी के बेशर्म नेताओं के बहुत ही घटिया बयान थे । जैसे चार बच्चों की माँ से भी कोई बलात्कार करता है ?

जिस गंगा के नाम पर ये राजनीति करते रहे उसकी निर्मलता के लिए प्रो.जीडी अग्रवाल ने जान दे दी फिर भी इनको कोई असर नहीं हुआ । अगर ये लोग विपक्ष में होते और इस तरह कोई हिन्दू सन्त गंगा की निर्मलता के लिए अपनी जान देता तो ये लोग आसमान सर में उठा लेते । बलात्कार के मुद्दों पर रात दिन आंदोलन करने वाले (हिमाचल कोटखई, निर्भया आदि मामलों में) ये लोग सत्ता में आते ही बलात्कारियों के समर्थन में उतर पड़े । नीचता की कोई हद इन लोगों के लिए नहीं है । जो महिलाएं इन पार्टियों में हैं वे तो सत्ता और धन कमाने हेतु हैं मगर अन्य सभी स्त्रियां समझ लें कि दक्षिणपंथी पार्टी कोई भी हो वह महिलाओं के हित में सोच ही नहीं सकती क्योंकि दक्षिणपंथ पुरुषसत्ता को मजबूत करती है। बीजेपी घोर हिंदुत्ववादी (दक्षिणपंथी) पार्टी है अत: महिलाएं इनके राज में जब तक घर की दीवारों के अंदर रहेंगी तब तक ठीक हैं, देवी हैं , जब तक अपने साथ हुए शोषण के खिलाफ चूँ भी नहीं करती तब तक देवी है , ज्यों ही उसने आवाज उठाई वह कुलटा है । आश्चर्य होता है जब महिलाएं इस तरह की घोर दक्षिणपंथी, पुरुषवादी और सामंतवादी पार्टी का समर्थन करती हैं ।

ये महिलाओं को कभी न तो समानता दे सकते हैं न स्वतंत्रता और न ही न्याय , और जब शोषण करने वाला इनकी पार्टी का हो तो फिर पूरी पार्टी बेशर्मी से कुछ भी कर सकती है । विपक्षी पार्टी के किसी नेता पर इस तरह के आरोप लगे हों तो ये लोग राजनीति के लिए दंगे तक करवा देते । केरल में हम यही देख रहे हैं जहाँ महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं यहाँ तक कि इनके एक नेता ने महिलाओं को चीर देने तक की धमकी दे डाली है ।

कट्टरपंथी किसी भी देश और समाज के लिए नासूर के समान होते हैं । इनकी विचारधारा केवल नफरत और नफरत की होती है । लोकतंत्र और लोकतांत्रिक विचारों से इनका दूर - - दूर तक कोई नाता नहीं होता है और न्याय ? न्याय इनके चरित्र में है ही नहीं । गलती तो उन दलों की भी उतनी ही है जितनी बीजेपी की , कि अन्य दलों ने बीजेपी को दशकों तक धर्म की राजनीति करने दिया है । इस तरह की विचारधारा को गर्भ में ही कुचल देना चाहिए था मगर क्या कीजियेगा जिस कांग्रेस में उच्च जातीय लोगों का एकाधिकार था उन लोगों के भी अंदर से एक पैर हमेशा हिंदुत्व में ही रहा है और अब ये इतने अधिक मजबूत हो चुके हैं कि इन पर अंकुश लगाना असंभव लगता है ।

लेकिन, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है । जिस हिंदुत्व की राजनीति ये करते आये हैं वही हिन्दू इनसे बहुत जल्द तंग आ जाएंगे , गुजरात तो बानगी भर है । अलगाव , विभाजन और नफरत हमेशा विभाजन ही करते हैं । हमारी पूरी संवेदना गुजरात में मारे गए बिहार के व्यक्ति के प्रति है जिसको पीट-पीट कर मार डाला गया । हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट देने वाले यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि धर्म की राजनीति केवल वोटों के लिए है , उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए नहीं ।

सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों को एक एक कर ठिकाने लगाया जा रहा है

गिरीश मालवीय

अब मोदी सरकार ओएनजीसी पर निगाहे गाड़ कर बैठी हुई है। ओएनजीसी देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कम्पनी है। इसका नाम कुछ दिनो पहले चर्चा में आया था जब ओएनजीसी के गैस क्षेत्र से रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा कथित तौर पर गैस निकाल लिये जाने के मामले में सरकार द्वारा रिलायंस से 1.50 अरब डॉलर की मांग को मध्यस्थता अदालत ने खारिज कर दिया था।

सरकार ने उस मामले में भी कोई इंटरेस्ट नही दिखाया था लेकिन जिस तरह से अब सरकारी कंपनी से मोदी सरकार जिस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज देश की गैस और तेल की जरूरत को पूरा करने में सर्वाधिक योगदान देने वाली कंपनी को अब ओवर ड्राट के माध्यम से अपने कर्मचारियों का वेतन देना पड़ रहा है।

दरअसल 2017 में मोदी सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे कि देश की सरकार को हजारों करोड़ का लाभ कमा कर देने वाला उपक्रम खुद कर्ज के जाल में फंसकर रह गया।

ओएनजीसी सरकार की सबसे अधिक कमाई करने वाली कंपनी है, इसके पास काफी अतिरिक्त पैसा भी था इसलिए 2017 में उसे सरकार की एक ओर कम्पनी एचपीसीएल को खरीदने के लिए बाध्य किया गया, इस सौदे में उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। लेकिन इसके बाद भी कंपनी को तकरीबन 20,000 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंकों से जुटाने पड़े जबकि कुछ समय पहले उसे घाटे में चल रही गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को भी 7,700 करोड़ रुपये में खरीदने को कहा गया था।

इन दोनों सौदों से ओएनजीसी की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती गयी अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोलियम कम्पनियों पर तेल की कीमत 1 रुपये कम करने का दबाव डाला उससे ओएनजीसी के शेयर की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है। सरकारी क्षेत्र की 41 कंपनियों के शेयर 52 हफ्ते के उच्चस्तर से आधे हो गए हैं।

ऐसे कड़े वक्त मे ओएनजीसी के कर्मचारियों के संघ की चिठ्ठी सामने आई है जो उन्होंने PMO को लिखी है। ओएनजीसी कर्मचारी मजदूर सभा उस चिठ्ठी में लिख रही है कि केंद्र सरकार के दखल के कारण ओएनजीसी भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रही है। कंपनी की मर्जी के बिना ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को उनकी पात्रता के बिना ही कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया है।

केंद्र सरकार की जिन योजनाओं में सरकार को पैसा लगाना चाहिए, उसमें दबाव बनाकर ओएनजीसी का पैसा लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के मंत्री लगातार दबाव बनाकर कंपनी से पैसा लेकर खर्च करा रहे हैं, एलपीजी कनेक्शन वितरण हो, शौचालय बनाना हो, गांवों को गोद लेना हो या लड़कियों के लिए सैनिट्री नैपकिन वितरण हो, हर काम के लिए सरकारी योजनाओं के फंड के बजाए ओएनजीसी के सीएसआर का पैसा लगाने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

इस मजदूर सभा के अध्यक्ष ताडवी ने लिखा है, "कर्मचारियों के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरण ओएनजीसी पहले एक विदेशी कंपनी से खरीदता रहा है, लेकिन अब तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसे किसी एक खास भारतीय कंपनी से खरीदने का दबाव बना रहे हैं। जबकि इस भारतीय कंपनी के उपकरण हमारी जरूरत पूरी नहीं करते।" अब यह घोटाला नही है तो ओर क्या है।

खबर (दार) झरोखा

लोकमित्र गौतम

अमेरिका से शुरू होकर अरब के रास्ते भारत पहुंचे 'मी टू' ने लिया आंदोलन का रूप

यौन शोषण की आपबीती कहानियों का पिछले साल अक्टूबर 2017 से पर्याय बन गया हैश मी टू आंदोलन 10 साल पहले शुरु हुआ था। इसकी शुरुआत अमरीका की सामाजिक कार्यकर्ता तराना बर्के ने किया था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके द्वारा रचा गया यह मुहावरा 'मी टू' यौन महिलाओं का सबसे बड़ा संबल बन जायेगा। उन्होंने तो इस मुहावरे की रचना सोशल मीडिया का महिलाओं के सशक्तिकरण में इस्तेमाल के लिए किया था। साल 2006 में तराना बर्के ने पहली बार माई स्पेस सोशल नेटवर्क में 'मी टू' के साथ कोई बात कहने की कोशिश की थी, जिसका मकसद था समाज के हाशिए में पड़ी महिलाओं का दुनिया की सहानुभूति के जरिए उत्थान करना संभव बनाया जाये।

इस मुहावरे ने हाशिए की महिलाओं का कितना सशक्तिकरण किया यह तो नहीं पता लेकिन पिछले साल अक्टूबर में जब हॉलीवुड के एक चर्चित प्रोड्यूसर के शोषण की कहानियों को इस मुहावरे के साथ सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया तो देखते ही देखते यह मुहावरा आपबीती दास्तानों का तूफान बन गया। जब यौन पीड़ित महिलाओं ने अपनी आपबीती दुनिया को सुनाने के लिए सोशल मीडिया में हैशटैग मी टू के साथ अपनी कहानियां डाली तो देखते ही देखते ये तीन शब्द सजगता और सशक्तिकरण के सबसे बड़े हथियार बन गये।

यह सब तब हुआ जब इसे हॉलीवुड के चर्चित प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन से शोषित महिलाओं ने अपनी कहानियां दुनिया को सुनाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इस मुहावरे का इस्तेमाल इसके पहले भी ऐसी ही आपबीती के लिए हो चुका था, लेकिन तब यह इतना चर्चित नहीं हुआ था। हैशटैग मी टू का इस्तेमाल अपनी यौन पीड़ित कहानी को दुनिया के साथ साझा करने के लिए पहली बार जेसिका एडम्स नाम की महिला ने किया। गौरतलब है कि अमरीका के एक मशहूर संगीतकार जोर्डी व्हाइट ने जेसिका के साथ बलात्कार और यौन हिंसा की थी।

जिसे जेसिका ने ज्यों का त्यों लिखकर सोशल मीडिया में हैशटैग मी टू शीर्षक के साथ डाल दिया था। इसे पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा। लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। बाद में 24 अक्टूबर 2017 को मर्लिन मैनसन ने और फिर इसके बाद एश्ले जुड नाम की हॉलीवुड हीरोइन ने अपने यौन शोषण की आपबीती सुनाने के लिए इसे इंटरनेट में डाला, तो हंगामा खड़ा हो गया। देखते ही देखते इसे दुनिया की लाखों महिलाओं ने पढ़ा और आपस में शेयर किया साथ ही वे अपने साथ भी घटी ऐसी ही घटनाओं को इंटरनेट में हैशटैग मी टू के साथ डालने लगीं।

इंटरनेट में मानो ऐसी आपबीती कहानियों का सैलाब आ गया। दुनिया के कोने-कोने से महिलाएं अपने दिल के अंधेरे कोनों में पड़ी ऐसी कहानियों को निकालकर सोशल मीडिया के उजाले में ले आयीं। देखते ही देखते यह ट्रेंड इतना तेज हो गया कि पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में आते-आते हर मिनट में ऐसी औसतन 10 कहानियां इंटरनेट में प्रेषित की जाने लगीं।

एक अनुमान है कि अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने जीवन में अपने साथ हुए यौन शोषण की त्रासदी को इंटरनेट में डाला है। यहां तक कि इस आंदोलन ने कट्टर मुस्लिम देशों की महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपनी आपबीती कहानियां इंटरनेट के जरिये पूरी दुनिया को बतायें।

सबसे पहले सोशल मीडिया में मुस्लिम दुनिया की ऐसी त्रासद कहानी लेकर लेखिका और पत्रकार मोना टाह्वी आयीं, उन्होंने सोशल मीडिया में आपबीती लिखा, 'साल 2013 में मैंने हज यात्रा की थी। उस दौरान मेरा यौन शोषण हुआ। मैं सालों तक यह क्रूर हादसा अपने सीने में छिपाये रखा। लेकिन जब मैंने मी टू हैशटैग कैंपेन के चलते तमाम महिलाओं की कहानियां पढ़ी तो मैं भी अपने साथ घटी इस कहानी को सोशल मीडिया में लाने से खुद को नहीं रोक सकी।'

मोना टाह्वी के मुताबिक जब उन्होंने ट्वीटर पर अपनी कहानी डाली तो इसे पढ़कर एक मुस्लिम महिला ने लिखा कि उनकी मां के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन हम लोगों के पास रोने के सिवा और कुछ नहीं था। यह बात फारसी ट्वीटर पर 10 से ज्यादा बार ट्रेंड हुई।

इसके बाद तो मुस्लिम महिलाओं ने भी आपबीतियों की झड़ी लगा दी। करीब 20 लाख मुसलमान हर साल हज के लिए जाते हैं, इनमें बढ़े पैमाने पर महिलाएं भी होती हैं और इन महिलाओं के साथ यौन शोषण की तमाम कहानियां वैसे ही घटित होती हैं जैसे दूसरी जगहों में महिलाओं के साथ होती थी। सोशल मीडिया में मुस्लिम महिलाओं ने यह अभियान हैशटैग मास्क मी टू के तहत लिखकर के किया। हालांकि मुस्लिम जगत में तमाम पुरुषों ने इस पर बहुत हंगाम किया। कई सरकारों ने भी इसे महिलाओं की उद्दंडता समझी। लेकिन आपबीती के इस ग्लोबल तूफान को कोई नहीं रोक पाया।

बहरहाल मी टू हैशटैग आंदोलन ने किसी एक देश, किसी एक समाज को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। करोड़ों-करोड़ कहानियों ने यह खुलासा कर दिया है कि हम चाहे सभ्यता और शिष्टता के कितने ही मुखौटे क्यों ओढ़े रहते हों, लेकिन मुखौटों के भीतर हम सदियोंपूर्ण के बर्बर इंसान ही हैं। हालांकि इस अभियान को कुछ लोगों ने एक प्रायोजित अभियान भी बताया और यह भी कहा कि इससे महिलाएं ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर होती हैं।

बावजूद इसके इस अभियान को रोका नहीं जा सका और यह भी कहा जा सकता है कि इस अभियान में दुनियाभर की महिलाओं को बहुत सजग बनाया है, एक किस्म से इस अभियान का फायदा यौन शिक्षा और सजगता के रूप में मिली है। इस अभियान के बाद दुनिया के तमाम देशों के स्कूलों में विशेष रूप से लड़कियों के लिए यौन शिक्षा देना शुरु किया गया साथ ही इन कहानियों से पुरुष भी महिलाओं के प्रति पहले से कहीं ज्यादा सहयोगी और ईमानदार हुए हैं।

अकबर मामले में रवीश ने लिखा राज्यसभा के सभापति को पत्र, पूछा-हेडमास्टर के नाते आपकी क्या है भूमिका

आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और उपसभापति जी,

आप राज्य सभा, जिसे उच्च सदन कहते हैं, के सभापति हैं। आपके सदन के सदस्य मुबशिर जावेद अकबर पर सोलह महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। उनके साथ दि एशियन एज की बीस महिला पत्रकारों ने अदालत में गवाही देने की बात कही है। अकबर के खिलाफ़ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। ऐसा कब हुआ है कि सोलह महिला पत्रकारों ने एक पूर्व संपादक पर क़रीब-क़रीब एक ही क़िस्म के आरोप लगाए हैं। वो संपादक अब आपके सदन का माननीय सदस्य है। उन्हें मध्य प्रदेश की जनता के अप्रत्यक्ष वोट से सदन में भेजा गया है।

हम समझते हैं कि देश में क़ानून की अपनी प्रक्रिया है। मगर मी टू अभियान बिल्कुल नई बात है। अगर यह अभियान न होता तो अलग अलग शहरों और आर्थिक परिवेश से आई सोलह महिलाएं कभी अकबर के खिलाफ़ नहीं बोल पातीं। भारत सरकार की मंत्री मेनका गांधी ने भी पूर्व जजों की कमेटी बनाकर जनसुनवाई की बात कही थी। आप हम उससे असहमत हो सकते हैं लेकिन आप मानेंगे कि मी टू के तहत लगाए गए पुराने आरोपों पर नई प्रक्रिया और प्रतिक्रिया की ज़रूरत है।

आप अपने सदन के सदस्य के ऊपर लगाए गए आरोपों पर क्या क़दम उठाने वाले हैं? क्या आप कमेटी बनाएंगे? क्या आप सदन के सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन करेंगे जिसमें बताया जाए कि एक औरत के साथ सांसदों को कैसे बर्ताव करना चाहिए। किसी महिला की 'ना' का मतलब क्या होता है? यौन उत्पीड़न क्या होता है? क्या राज्य सभा में सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन के अनुसार कोई कमेटी है? नहीं है तो क्यों नहीं है?

मैं यह सार्वजनिक पत्र इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप जवाब सार्वजनिक रूप से दें। जिससे जनता में भरोसा हो कि भारत की संसदीय प्रणाली के उच्च सदन में कोई ऐसा सदस्य न आ जाए जिस पर सोलह महिला पत्रकार अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के आरोप लगाएं। हम आरोप को आरोप समझते हैं मगर सदन के हेडमास्टर होने के नाते इस प्रकरण में आपकी क्या भूमिका है? क्या आप पार्टियों को लिखेंगे कि किसी को राज्य सभा की सदस्यता देते समय ठीक से पड़ताल करें। क्या आप सभी सदस्यों को पत्र लिखेंगे कि महिला सदस्यों और महिलाओं के साथ क्या आचरण होना चाहिए?

आप दोनों से जनता को बहुत उम्मीदें हैं। आपके जवाब का इंतज़ार है। हो सकता है कि संसदीय परंपरा के तहत मेरे सवालों के जवाब न हों। मगर मैं आग्रह करता हूं कि आप जवाब दें। जवाब देने की कोशिश करें। यक़ीन जानें एक नई परंपरा बनेगी। वो शानदार परंपरा होगी।